लूट कमाई के लिए न्यायपालिका को भी गुमराह कर रहे निगम अधिकारी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। आवासीय क्षेत्र या आवासीय भवन में चलाए जा रहे प्री प्राइमरी स्कूलों को न्यायालय के आदेश पर सील करने और फिर सुविधा शुल्क लेकर सील तुड़वाने का धंधा नगर निगम अधिकारी बीते चार वर्ष से चला रहे हैं। स्कूलों से मोटी कमाई कर रहे निगम अधिकारी इनको सील किए जाने की रिपोर्ट पेश कर न्यायालय को भी गुमराह कर रहे हैं।शहर के आवासीय क्षेत्र या आवासीय भवनों में नियम विरुद्ध रूप से चलाए जा रहे प्री प्राइमरी, प्ले ग्रुप स्कूलों को सील करने की कार्रवाई पूर्व निगमायुक्त एम शाइन के कार्यकाल में की गई थी। उच्च न्यायालय के आदेश पर निगम टीम ने आवासीय इलाकों या परिसर में चल रहे ऐसे 25 स्कूलों को चिह्नित किया था। इनमें से आवासीय भवन में चल रहे नौ स्कूलों को सील कर दिया गया था जबकि बाकी स्कूलों को नोटिस जारी कर उन्हें बंद करने के आदेश जारी किए गए थे।

निगम सूत्रों के अनुसार न्यायालय में सीलिंग की कार्रवाई की रिपोर्ट पेश किए जाने के कुछ समय बाद ही तोड़फोड़ विभाग के तत्कालीन कर्मचारियों ने सुविधा शुल्क लेने के बाद इन स्कूलों की सीलें तुड़वा दीं और इनमें शिक्षण कार्य सुचारू हो गया।

अभिभावकों से मोटी फीस वसूलने वाले स्कूलों की कमाई न रुके इसलिए तब से यह काम इसी तरह चल रहा है। हर बार न्यायालय में सुनवाई के समय इन स्कूलों के मेन गेट सील कर फोटो के साथ अपडेट पेश कर दी जाती हैं। बताया जा रहा है कि अब इन स्कूलों से सुविधा शुल्क वसूलने का काम तोड़फोड़ विभाग के बेलदार अमरपाल के पास है। कहने को तो वो बेलदार है लेकिन ठाठबाट किसी अधिकारी से कम नहीं है।

नगर निगम में उसे तोड़फोड़ दस्ते का वसूली अधिकारी कहा जाता है क्योंकि वह ही तोड़फोड़ की नोटिस देने और फिर कार्रवाई न करने के एवज में रकम तय और वसूल करता है। वसूली के बाद यह रकम विभाग के अधिकारियों से लेकर ऊपर तक बंटती है।

बीते सितंबर में भी सुनवाई के दौरान निगम अधिकारियों ने स्कूलों के सील होने की रिपोर्ट लगा दी, अब मामले की सुनवाई फरवरी 2024 में होनी है। तब तक स्कूलों की सील फिर टूट चुकी होगी।

युद्धवीर मीतू सैनी वार्ड 14 से नगर पार्षद करनाल की ओर से नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

राकेश नागपाल एक्स चेयरमैन नगर सुधार मंडल करनाल की ओर से नगर वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

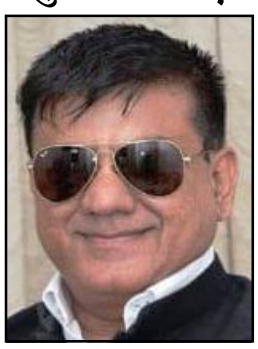

मुकेश कुमार (समाज सेवी) मैसर्स शांति मेडिसिन करनाल की ओर से करनाल वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं

प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर दोबारा घोटाले की तैयारी

फ़रीदाबाद (मज़दूर मोर्चा)। जनता की गाढ़ी कमाई संघ-भाजपा समर्थकों द्वारा कैसे लूटी जाए, ये खट्टर सरकार बाखूबी जानती है। भाजपा-संघ से जुड़ी याशी कंसल्टेंसी को प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर खट्टर सरकार ने 57 करोड़ रुपये का ठेका दे दिया। अनुभवहीन कंपनी प्रॉपर्टी आईडी बनाने के नाम पर उल्टे सीधे आंकड़े पेश कर करीब एक साल पहले भुगतान वसूल कर चलती बनी।

संघ-भाजपा का चहेता होने के कारण खट्टर सरकार ने भी याशी कंसल्टेंसी का न तो भुगतान रोकने का फरमान सुनाया और न ही उसे ब्लैक लिस्ट करने की जहमत उठाई। सीएम खट्टर ने कंपनी को सभी जिलों में प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त करने के भी निर्देश नहीं दिए उल्टे पूरा भुगतान करवा दिया गया।

प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर करोड़ों लुटाने के बाद अब सरकार इन्हें दुरुस्त कराने के नाम पर भी करोड़ों रुपये लुटाने जा रही है। बताया जा रहा है कि इसके लिए सरकार ने सिंप्लेक्स सोल्यूशंस नाम की कंपनी को ठेका दिया जाना तय किया है। कंपनी को प्रॉपर्टी आईडी में सुधार करने का ठेका दिए जाने से नगर निगम कर्मचारियों में चर्चाओं का दौर चल पड़ा है। कर्मचारियों के अनुसार याशी कंसल्टेंसी से पहले प्रॉपर्टी आईडी बनाने का काम इसी कंपनी को दिया गया था। तब भी घर घर जाकर प्रॉपर्टी आईडी के भौतिक आंकड़े इकट्ठा करने थे लेकिन तब कंपनी के कर्मचारियों ने घर बैठे-बैठे कागजों पर ही सर्वे कर डाला था। कंपनी की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर आम जनता और नगर निगम के अधिकारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। कंपनी की गड़बड़ियां पकड़े जाने पर सभी जेडटीओ ने रिपोर्ट तैयार कर निगमायुक्त को सौंपी थी। बताया जाता है कि निगमायुक्त ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश सरकार से की थी। कंपनी को ब्लैक लिस्ट करने के बजाय अस्थायी रूप से डीलिस्ट कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि अब इसी कंपनी को दोबारा से प्रॉपर्टी आईडी दुरुस्त करने का काम सौंपा जा रहा है।

निगम अधिकारियों के अनुसार यह कंपनी घर-घर पहुंच कर प्रापर्टी आईडी में क्या क्या कमियां हैं, पता करने के लिए प्रॉपर्टी असेसमेंट नोटिस जारी करेगी। प्रॉपर्टी मालिक द्वारा लगाई गई आपत्ति के संबंध में जरूरी दस्तावेज भी तलब करेगी। सारे दस्तावेज पूरे होने के बाद कंपनी नई प्रॉपर्टी आईडी जारी करेगी। सर्वविदित है कि इस कंपनी ने पहली बार भी घर-घर न जाकर कागजों पर ही सारी प्रॉपर्टियों के फर्जी आंकड़े बना डाले थे। निगम कर्मियों में चर्चा है कि प्रॉपर्टी आईडी के नाम पर दोबारा घोटाले की नींव न रखी जा रही हो। कहीं ऐसा न हो कि कंपनी भी याशी कंसल्टेंसी की तरह भुगतान लेकर भाग जाए और आम जनता व नगर निगम अधिकारी फिर परेशान होते फिरें।

पूरी ताकत झोंकने के बाद भी असफल रहा अंत्योदय सम्मेलनः कुलदीप शर्मा

करनाल। सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के बावजूद करनाल में करनाल में भाजपा का अंत्योदय सम्मेलन पूरी तरह विफल रहा। इतने बड़े सम्मेलन में केवल चार हजार लोग ही पहुंचे, उनमें भी सरकारी कर्मचारी, भाजपा नेता और जबरन इकट्ठा कर लाए गए लोग ही अधिक थे आम जनता ने तो सम्मेलन को नकार दिया! ये दावा हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने किया।

एक प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि सीएम मनोहर लाल खट्टर को अपनी कुर्सी छिनने का डर है। भयभीत सीएम ने अमित शाह को खुश करने के लिए सम्मेलन किया और उसमें भीड़ जुटाने के लिए पूरे दांव पेंच लगाए लेकिन कामयाब नहीं हो सके। गृहमंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने भाषण के दौरान एक बार भी दीनदयाल उपाध्याय का नाम नहीं लिया जबकि ये सम्मेलन ही दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया था। अमित शाह मोदी और भाजपा की जय-जयकार करवाने में लगे थे, लेकिन सम्मेलन में मौजूद लोगों ने नारे नहीं लगाए।

कुलदीप शर्मा ने कहा कि सम्मेलन से पहले भाजपा के लोग झूठा प्रचार कर रहे थे कि अमित शाह हरियाणा में चार नए जिले बनाने, एसवाईएल को लेकर बड़ा एलान करने, पेंशन 5100 रुपए करने तथा महिलाओं को घर चलाने के लिए दो हजार रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा करेंगे। हैरानी की बात है कि गृहमंत्री ने एक भी घोषणा नहीं की।

पर्चे और खर्चे वाली सरकार है भाजपा

कुलदीप शर्मा ने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरियां देने के दावे कर रही है। वास्तव में सबसे ज्यादे पर्चे और खर्चे इसी सरकार में चले हैं। परीक्षाओं के पेपर तैयार करने वालों ने ही पेपर लीक करने और बेचने का काम किया। हरियाणा में 32 से ज्यादा पर्चे लीक हुए हैं। इस अवसर पर पूर्व मंत्री भीम मेहता, पूर्व विधायक सुमिता सिंह, जिला संयोजक त्रिलोचन सिंह, रघबीर संधु, अशोक खुराना, मनिंद्र सिंह शंटी, पप्पू लाठर, हरीराम साबा, रणपाल संधु, सतपाल सरपंच जाणी, सतीश राणा, जागीर सैनी, ललित अरोड़ा, गगन मेहता, परमजीत वाल्मीकि, संतोष तेजान, नीलम मल्होत्रा, विनोद शर्मा व सतीश शर्मा मौजूद रहे।

सुप्रीम कोर्ट की फटकार से पंजाब सरकार सुधरे तो बात बने : डॉ. चौहान

करनाल। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के प्रवक्ता डॉ.वीरेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि दिल्ली को गैस चेंबर में तब्दील होने से रोकने में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार एक बार फिर असफल रही हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार को सीधे तौर पर फटकार लगाकर साफ़ कर दिया है कि भगवंत मान सरकार कोरी राजनीति कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर आम आदमी पार्टी को राजनीतिक हुड़दंग और प्रपंच से बाहर आने और धरातल पर काम करने के लिए आगाह करती है।

डॉ. वीरेंद्र सिंह चौहान ने यह टिप्पणी एक बयान मे ं की। उन्होंने उम्मीद जतायी कि सर्वोच्च न्यायालय की फटकार के बाद अब आम आदमी पार्टी की सरकार के निकम्मेपन पर अंकुश लगेगा लेकिन वह योगी और खट्टर सरकार के बारे में चुप्पी साध गए।

मानो इन सरकारों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार नहीं लगाई थी, और यूपी व हरियाणा में पराली जलाई ही नहीं जाती और सारा वातावरण सिर्फ पंजाब में जलाई जाने वाली पराली से खराब हुआ है।

डॉ. चौहान के मुताबिक भारत के सेटेलाइट चित्र पंजाबखेतों में बेहिसाब पराली दहन की घटनाएं दर्शा रहे हैं। उन्हें हरियाणा और पंजाब में जलती पराली नजर नहीं आई। मुश्किल से माना कि हरियाणा में पराली जलाई जा रही है लेकिन पंजाब पर निशाना साधते हुए बोले कि वहां मामले पांच गुना अधिक हैं।

डॉ. चौहान पराली का रोना तो रो रहे हैं लेकिन पटाखों पर जो प्रतिबंध लगा है उसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है, धर्म के नाम पर तो ये सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाकर भी पटाखे फोड़ सकते हैं। इन्हें धर्म के नाम पर हर तरह की गुंडागर्दी करने व झूठ बोलने की छूट है।

डॉ. चौहान केजरीवाल पर तो सवाल खड़े कर रहे हैं लेकिन उन्होंने सीएम खट्टर से एक बार भी प्रदूषण नियंत्रण करने की मांग नहीं की। डॉ. चौहान भी प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दे पराली-पराली खेल रहे हैं।